

प्रेस वृत्त

दिनांक: 25 सतंबर, 2018

राष्ट्रीय ई-वधान ऐपलीकेशन सदनों की कार्यवाहियों को डिजिटल बनाकर देश के सभी वधानमंडलों के कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लए संसदीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है। यह एक बटन दबाकर नागरिकों को सदन के कार्यचालन के बारे में सूचना उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। नेवा वेबसाइट के साथ नेवा की **iOS** और गूगल ऐप एक समान रूप में देश में सभी वधानमंडलों के कार्य से संबंधित आंकड़ों के निक्षेपागार के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक ऐपलीकेशन" होने की अपनी क्षमता को चरितार्थ करना है। डाटाबेस की यह एकरूपता सरकार के साथ नागरिकों के आसान और प्रभावी अनुबंध में परिणत होगी। नेवा वधानमंडलों के कार्यचालन को हमारे नागरिकों के करीब लाकर लोकतंत्र को उनके करीब लाएगी। नेवा वधानमंडलों को नागरिकों के नजदीक लाएगा और ऐसा करते हुए यह लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य व भन्न राज्य सरकार के वभागों के साथ सूचना आदान-प्रदान के लए सभी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाकर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वधानमंडलों को कागज रहित बनाना और सूचना को वास्तविक समय में पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। कार्य प्रक्रिया की पुनर्रचना आरंभ करने से यह सेवाओं के सफल परिदान में परिणत होगा और सभी हितधारकों की वश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगा। एक बार जब कार्यक्रम चालू हो जाएगा, **40** वधानमंडलों के **5379** सदस्यों का ववरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वधानमंडलों के **113337** प्रश्न, **25662** नोटिस, **1708** वधेयक, **515** समितियों के प्रतिवेदन और **10043** कागज-पत्र नेवा ऐप और वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो जाएंगे।

नेवा ऐपलीकेशन का खुलासा करने और ऐप का कार्य करने का तरीका दर्शाने के लए, संसदीय कार्य मंत्रालय के त्त्वावधान में **24-25** सतंबर को संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-वधान ऐपलीकेशन (नेवा) पर दो दिन की एक अभिव्यक्त कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में लोक सभा और राज्य सभा सचवालय सहित देश के 36 वधानमंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 200 से ज्यादा प्रतिभा गयों ने भाग लिया।

यह उस श्रृंखला की पहली कार्यशाला थी जिसकी योजना संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेवा की प्रभावी शुरुआत के लिए बनाई गई है। कार्यशाला का उद्घाटन श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। प्रतिभा गयों को अपने संबोधन में उन्होंने सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के आलोक में नेवा के अंगीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। सुश्री नीता वर्मा, महानिदेशक, एन.आई.सी. ने इस अवसर पर आधार व्याख्यान दिया।

इन दो दिनों की अवधि में, गण्यमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा नेवा की विशेषताओं के संबंध में महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए और संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। ऐपलीकेशन के प्रयोगात्मक प्रदर्शन सहित तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। एन.आई.सी. के विशेषज्ञों के सत्रों में नेवा ऐपलीकेशन के क्लाउड फर्स्ट और मोबाइल फर्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया। हिमाचल प्रदेश वधानसभा के साथ एक अनुभव साझाकरण सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार टीम ने परियोजना को कार्यान्वित करने फायदों के साथ-साथ उसकी चुनौतियों पर चर्चा की। सामूहिक चर्चा के माध्यम से प्रतिभा गयों के सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया गया। नेवा के त्वरित कार्यान्वयन पर सहमति बनकर उभरी।

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि नेवा ऐपलीकेशन सदस्य केंद्रित, प्रयोगकर्ता अनुकूल है और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि यह केवल एक शुरुआत थी और संसदीय कार्य मंत्रालय हर एक कदम पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लगातार मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सुचारू रूप से नए डिजिटल प्लेटफार्म पर जाने के लिए हर कदम पर सहायता मुहैया कराने के लिए एक समर्पित नेवा टीम बनाई गई है।

समापन समारोह की अध्यक्षता श्री वजय गोयल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्री अमताभ कांत, सी.ई.ओ., नीति आयोग द्वारा की गई। श्री अमताभ कांत ने इस पहल की सराहना की और नागरिकों को वधानमंडलों के कार्यचालन के संबंधी सूचना की आसान और कार्यसाधक पहुंच सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसका स्वागत किया। श्री वजय गोयल ने राज्यों से नेवा को खुले हाथों से अपनाने का अनुरोध किया और प्रतिभाग्यों से अपने गृह राज्यों में वापस जाने पर नेवा के मुखतार बनने का आह्वान किया। इस परियोजना को जल्द अपनाने में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन राज्यों अर्थात् पंजाब, गुजरात और कर्नाटक का सम्मानित किया गया।

संयुक्त सचिव, डॉ. सत्य प्रकाश ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन किया।